मिलेगी मदद या मचेगी अफरातफरी

उर्वरक सब्सिडी के लिए डीबीटी सुविधा से यह जरूरी नहीं कि विनिर्माताओं के भारी बकाये को कम करने में मदद मिले

संजीव मुखर्जी

सरकार ने इस साल अप्रैल से देश के 14 करोड़ किसानों को उर्वरक सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के जरिये अनिवार्य बनाने की योजना बनाई है। साथ ही डीबीटी लागू होने से पहले 31 मार्च, 2018 तक उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी के बकाये के भुगतान की भी बात कही गई है लेकिन इस तथ्य की ओर किसी का ज्यादा ध्यान नहीं है। 22 दिसंबर तक करीब 14 राज्यों को डीबीटी व्यवस्था के तहत लाया गया है। यह उर्वरक बनाने वाली कंपनियों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि पिछले कुछ सालों से सब्सिडी का बकाया उनके लिए सिरदर्द बना हुआ है और इससे उनकी कार्यशील पूंजी लागत भी प्रभावित हुई है। इस वित्त वर्ष के दौरान यह बकाया 280 अरब रुपये रहने की उम्मीद है जबकि वित्त वर्ष 2016-17 में यह 300 अरब रुपये थी। इसका कारण गैस की कम कीमत हो सकती है जिससे सब्सिडी जुड़ी हुई है।

लेकिन क्या राष्ट्रीय स्तर पर डीबीटी लागू करने से सब्सिडी बकाया तुरंत खत्म हो जाएगा? उद्योग के प्रतिनिधियों की मानें तो शायद ऐसा नहीं होगा क्योंकि पहले बुनियादी मुद्दों को हल करने की जरूरत है। पहली बात तो यह है कि गैस की कम कीमतों का दौर अब खत्म हो रहा है। गैस की कीमतों में 2017-18 की पहली छमाही में कमी आई थी लेकिन दूसरी छमाही में इसमें 10 से 15 फीसदी की तेजी आ चुकी है। अप्रैल में गैस की कीमतों की समीक्षा होगी। गैस की कीमतें बढ़ने का मतलब है कि उर्वरक कंपनियों की उत्पादन लागत बढ़ेगी क्योंकि उनके कच्चे माल की लागत में इसका योगदान 65 फीसदी है।

डीबीटी लागू होने से पहले 31 मार्च, 2018 तक खाद कंपनियों को सब्सिडी बकाये के भुगतान की भी बात कही गई है

इस बात पर भी संदेह है कि क्या डीबीटी प्रक्रिया से बकाया सब्सिडी कम करने में मदद मिलेगी या नहीं। इक्रा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और समूह प्रमुख (कॉर्पोरेट रेटिंग्स) के रविचंद्रन ने कहा, 'अभी उर्वरक की बोरियों के कारखाने से जिला मुख्यालयों की तरफ जाने पर बिलों को प्रोसेस किया जाता है। डीबीटी लागू होने पर भुगतान की प्रक्रिया उर्वरक के किसानों के पास पहुंचने के बाद शुरू होगी।'

रविचंद्रन उर्वरक सब्सिडी में डीबीटी व्यवस्था की बात कर रहे थे। रसोई गैस सब्सिडी उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा की जाती है जबकि उर्वरक सब्सिडी में डीबीटी व्यवस्था अलग तरह से काम करेगी। अगर किसान को अग्रिम भुगतान के बारे में जानकारी नहीं है तो वह पॉइंट ऑफ सेल्स (पीओएस) मशीनों से सब्सिडी वाली दर पर उर्वरक खरीद सकते हैं। यह मशीन लेनदेन को रिकॉर्ड करेगी। रिटेलर की वेबसाइट पर लेनदेन की जानकारी अपलोड होने के बाद सब्सिडी का भुगतान किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि डीबीटी के मौजूदा प्रारूप में उद्योग के लिए क्लीयरेंस का एक और स्तर जुड़ गया है। उर्वरक उद्योग से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जरूरत है, अन्यथा इससे अफरातफरी मच जाएगी।'

दो कारणों से अफरातफरी का माहौल बन सकता है। पहला है पीओएस मशीनों की उपलब्धता। जिन 14 राज्यों में डीबीटी के जरिये उर्वरक सब्सिडी दी जा रही है, उनमें रिटेलरों को करीब 130,000 पीओएस मशीनें दी गई हैं। सभी राज्यों में इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए मार्च, 2018 तक 200,000 से अधिक मशीनों की जरूरत होगी। उद्योग के सूत्रों का कहना है कि पीओएस की 60 फीसदी जरूरत पूरी की जा चुकी है और केवल 4-5 राज्यों को ही उन्हें स्थापित करना है।

दूसरा कारण यह है कि पीओएस लेनदेन को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया में आधार आधारित उर्वरक वितरण प्रणाली (एईएफडीएस) से जुड़ी कई दिक्कतें हैं। सरकार समर्थित संगठन माइक्रोसेव द्वारा 88 जिलों में 200 दुकानों पर किए गए अध्ययन के मुताबिक 88 फीसदी किसानों को जानकारी नहीं है कि उर्वरक खरीदने के लिए आधार कार्ड दिखाने की जरूरत है। साथ ही पहले प्रयास में केवल 35 फीसदी बायोमीट्रिक सत्यापन की सफल रहे।

संक्षेप में कहें तो एईएफडीएस खेती के मौसम में रोजाना 300 से 500 किसानों को संभालने में सक्षम नहीं है। इससे रिटेलरों के फर्जी लेनदेन पर उतरने का जोखिम है। यानी कोई और खरीदार के लिए सत्यापन करेगा जिससे व्यवस्था के दुरुपयोग की जमीन तैयार होगी, जिसे खत्म करने के लिए डीबीटी को लाया जा रहा है। उर्वरक बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि बकाया सब्सिडी को कम करने का सबसे आसान तरीका यह है कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। उदाहरण के लिए मालभाड़ा प्रतिपूर्ति संशोधन की अधिसूचना में कई महीने लग जाते हैं जिससे सब्सिडी के दावों में देरी होती है। सरकार उर्वरक की खपत कम करने के लिए दूसरे उपाय भी कर रही है। खासकर यूरिया की खपत घटाने का सरकार का सबसे ज्यादा जोर है। इस पर बहुत ज्यादा सब्सिडी मिलती है और यही वजह है कि देश में इसका सबसे अधिक इस्तेमाल होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हालिया रेडियो संबोधन में 2022 तक यूरिया का इस्तेमाल आधा करने की अपील की थी। देश में करीब 3 करोड़ टन यूरिया की खपत होती है। देश में अभी सालाना 2.4 करोड़ टन यूरिया का उत्पादन होता है और करीब 50 से 70 लाख टन यूरिया आयात करना पड़ता है। अगर यूरिया की खपत में कमी आती है तो इसका आयात नहीं करना पड़ेगा। पिछली सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए थे जिन्हें इस सरकार ने तेज किया है। 2015 में सरकार ने सभी कंपनियों के लिए यूरिया को नीम कोट करना अनिवार्य बना दिया था। इससे यूरिया से नाइट्रोजन से अलग होने की प्रक्रिया धीमी होगी और इसका अधिकम इस्तेमाल हो सकेगा। साथ ही दूध में मिलावट जैसे दूसरे कामों में इसका इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। इस योजना के तहत 50 किलो के बजाय 45 किलो की बोरियों में यूरिया को पैक किया जा रहा है। कागज पर भले ही ये कदम मजबूत दिख रहे हैं लेकिन हकीकत में इनसे अपेक्षित परिणाम नहीं निकला।

उदाहरण के लिए नीम कोटिंग यूरिया में करीब 10 फीसदी यूरिया खपत की बचत करने और मिट्टी की उर्वर शक्ति में सुधार करने की क्षमता है। उद्योग के जानकारों का कहना है कि शुरुआती अध्ययनों के मुताबिक कुछ राज्यों में नीम कोटेड यूरिया के कारण उत्पादन में सुधार आया है लेकिन इसका कोई निर्णायक सबूत नहीं है। बेंगलूरु के इंस्टीट्यूट फॉर सोशियो-इकनॉमिक चेंज द्वारा कराए गए एक अध्ययन के मुताबिक अधिकांश धान किसानों ने मृदा स्वास्थ्य और उपज की गुणवत्ता में सुधार की बात स्वीकार की लेकिन 80 फीसदी से अधिक चना किसानों ने कहा कि उनके उत्पादन में कोई बदलाव नहीं आया है। जब सामान्य यूरिया के बजाय नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल किया गया तो धान के लिए अन्य उर्वरकों की कीमत में 15 फीसदी और चने के लिए अन्य उर्वरकों में 50 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। मृदा स्वास्थ्य कार्ड से भी किसानों के उर्वरकों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने की संभावना है। अभी तक 10 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। लेकिन उर्वरक बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि जब तक सरकार मिट्टी की वैज्ञानिक मानचित्रण नहीं करती है और किसान कार्ड की सिफारिशों के मुताबिक काम नहीं करते हैं, तब तक मृदा स्वास्थ्य कार्ड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

डीबीटी के प्रभाव, उर्वरक की खपत में कमी के लिए नीम कोटेड यूरिया, उर्वरक की छोटी बोरियों और मृदा स्वास्थ्य कार्ड के इस्तेमाल पर संदेह गहरा रहा है क्योंकि खाद्य की बढ़ती मांग के कारण भारत में उर्वरक की खपत अगले दशक में कम से कम 20 फीसदी बढ़ने की संभावना है। घरेलू स्तर पर उर्वरक का उत्पादन बढ़ाना घरेलू उद्योग की विस्तार करने की क्षमता पर निर्भर करता है। साथ ही यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि सरकार बंद पड़े 8 खाद कारखानों में फिर से उत्पादन शुरू करने के लिए क्या कदम उठाती है।

पिछड़े इलाकों में पढ़ाएंगे आईआईटी के छात्र

प्रकाश जावड़ेकर

साहिल मक्कड़

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) और भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) के हाल में पढ़ाई पूरी कर निकले छात्रों को 53 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने के लिए चुना है। देश के 11 पिछड़े राज्यों में करीब 1,225 सहायक प्रवक्ता का पद रिक्त है। पीएचडी डिग्री वाले 293 छात्रों और एमटेक की डिग्री वाले 932 छात्रों ने अनुंबध के आधार पर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया है और उनका मासिक वेतन 70,000 रुपये है। हालांकि उनके वेतन का भुगतान विश्व बैंक से सहायताप्राप्त उस परियोजना के जरिये होगा जिसके तहत बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में इंजीनियरिंग के स्नातक छात्रों की गुणवत्ता में सुधार करना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि इन छात्रों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया है क्योंकि अनुबंध वाली नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण देने का प्रावधान लागू नहीं होता है। हालांकि सरकार ने तीन साल का अनुबंध पूरा होने के बाद इन छात्रों को रोजगार देने की योजना का कोई ब्योरा नहीं दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कहना है, 'शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए पहली बार ऐसा कदम उठाया जा रहा है। इससे अति पिछड़े इलाके में करीब एक लाख इंजीनियरिंग छात्रों को मदद मिलेगी।' जावड़ेकर का कहना है कि करीब 5,000 छात्रों ने इन पदों के लिए आवेदन दिया। उन्होंने कहा, 'कड़ी चयन प्रक्रिया के जरिये इनका चयन किया गया। बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश और ओडिशा के बेहद महत्त्वाकांक्षी 7 जिलों में बेहतरीन शिक्षकों को भेजा गया है।'

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक
www.bankofbaroda.co.in

निविदा-सूचना

बैंक ऑफ़ बड़ौदा, प्रधान कार्यालय, बड़ौदा -1- वर्ष के लिए हमारे एप्पैनल्ड प्रिंटरों को माइकर सिक्योरिटी पेपर की आपूर्ति हेतु लागत बोली कोट करने के लिए **आईबीए अनुमोदित तथा पेपर मिलों द्वारा नामित पेपर निर्माताओं/मिलों/वितरकों से** निविदा आमंत्रित करता है.

निविदा में किसी भी परिशिष्ट सहित कोई भी संशोधन/सुधार/परिवर्तन होने पर केवल बैंक की वेबसाइट में ही सूचित किया जाएगा. इच्छुक बोली लगानेवाले को प्रस्ताव की अंतिम प्रस्तुति से पहले वेबसाइट को देख लेना चाहिए.

निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख दिनांक 22-02-2018 को शाम 05.00 से पहले है. विस्तृत विवरण के लिए **www.bankofbaroda.co.in** पर लॉग ऑन करें और **Tenders** लिंक पर जाएं.

स्थान: बड़ौदा
दिनांक: 01.02.2018

सहायक महाप्रबंधक
(परिचालन एवं सेवाएं)
प्रधान कार्यालय, बड़ौदा
(103/17-18)

Kajaria
TRANSFORM YOUR WORLD

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2017

(₹ in crores, except per share data)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended 31 December 2017 (Unaudited)	Nine Months Ended 31 December 2017 (Unaudited)	Quarter Ended 31 December 2016 (Unaudited)
1	**Income**			
	a) Revenue from Operations	661.16	2032.51	677.08
	b) Other income	1.77	5.70	2.10
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	84.25	256.91	85.85
3	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	84.25	257.66	85.85
4	Net Profit for the period after Tax, (after Exceptional and/or Extraordinary items and after minority interest)	54.31	168.99	55.11
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	53.93	167.39	55.11
6	Equity Share Capital (Face value of ₹1/- per share)	15.89	15.89	15.89
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	1159.23 (as on 31 Mar 17)	1159.23 (as on 31 Mar 17)	956.01 (as on 31 Mar 16)
8	Earnings per share (of ₹1/- each) (for continuing and discountinued operations)			
	a) Basic:	3.42	10.63	3.47
	b) Diluted:	3.41	10.60	3.46

Notes:

1 The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 31 January 2018 and have undergone 'Limited Review' by the statutory auditors of the Company.

2 The above results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ('Ind AS') as notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, amended by the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2016, specified under section 133 of the Companies Act, 2013.

3 **Additional information on standalone financial results is as follows:** ₹ in crores

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended 31 December 2017 (Unaudited)	Nine Months Ended 31 December 2017 (Unaudited)	Quarter Ended 31 December 2016 (Unaudited)
1	**Income**			
	a) Revenue from Operations	624.05	1926.89	645.40
	b) Other income	5.16	14.60	5.86
2	Net Profit before Tax	90.45	283.26	89.84
3	Net Profit After Tax	59.58	186.64	60.51
4	Total comprehensive income for the period	59.20	185.04	60.51

4 Post the applicability of Goods and Services tax (GST) with effect from 1 July 2017, Revenue from operations are required to be disclosed net of GST in accordance with the requirements of Ind AS. Accordingly the Revenue from operations for the quarter ended and nine months ended 31 December 2017 are not comparable with the corresponding previous quarter/nine months presented in the financial results which are reported inclusive of Excise Duty.

5 The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter and nine months ended 31 December 2017 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results are available on the website of BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the Company's website at www.kajariaceramics.com

Place: New Delhi
Date: 31 January 2018

For and on behalf of the Board
Ashok Kajaria
Chairman & Managing Director

KAJARIA CERAMICS LIMITED
Regd. Office: SF-11, Second floor, JMD Regent Plaza, Mehrauli-Gurgaon Road, Village Sikanderpur Ghosi, Gurgaon -122001 (Haryana)
Corporate Office: J-1/B-1 (Extn), Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044
Ph.: 91-11-26946409 | Fax: 91-11-26949544, 91-11-26946407
CIN: L26924HR1985PLC056150, E-mail: investors@kajariaceramics.com, Website: www.kajariaceramics.com

PAISALO DIGITAL LIMITED

FORMERLY KNOWN AS S. E. INVESTMENTS LIMITED

REGD. OFF: 101, CSC, POCKET 52, NEAR POLICE STATION, CR PARK, NEW DELHI-110019
TEL: +91 11 43518888 FAX: + 91 11 43518816 WEB: www.paisalo.in
CIN: L65921DL1992PLC120483

अर्थः समाजस्य न्यासः

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE) FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2017

(₹in Lacs)

Particulars	Quarter Ended 31.12.2017 (Unaudited)	Nine Months Ended 31.12.2017 (Unaudited)	Quarter Ended 31.12.2016 (Unaudited)
Total income from operation (net)	7690.48	21620.20	6304.17
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2115.20	6577.91	2024.36
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2115.20	6577.91	2024.36
Net Profit/(Loss) for the period after tax	1749.32	5648.12	1606.13
Equity Share Capital	4056.00	4056.00	4056.00
Reserves* (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of Previous Year)	—	—	—
Basic and diluted earning per share (in Rs.) (before and after extraordinary items (not annualised) (Face value of Rs. 10/- each)	4.31	13.93	3.96

* Reserves (excluding Revaluation Reserve) as on 31.03.2017 was Rs. 51356.30 lacs.

Note:

The above is an extract of the detailed Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Company's website i.e. www.paisalo.in and on the Stock Exchanges' websites i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com

Place: New Delhi
Date : 30.01.2018

For and on behalf of Board of Directors
Sd/-
(SUNIL AGARWAL)
Managing Director

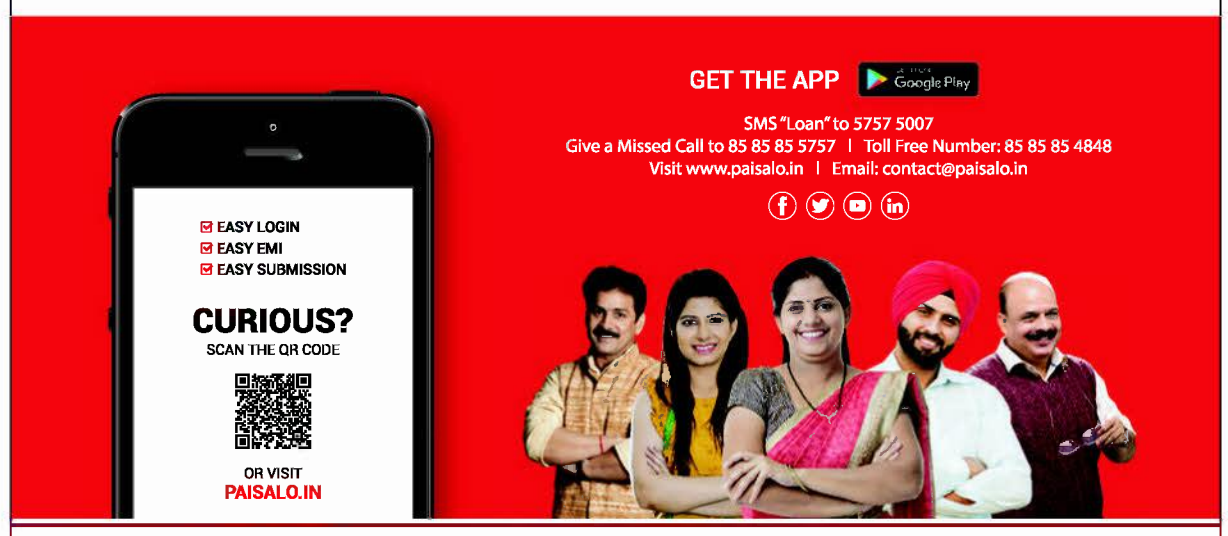

PAISALO
EASY LOAN आसान लोन

SUPER BLUE BLOOD MOON

PHOTO: PTI

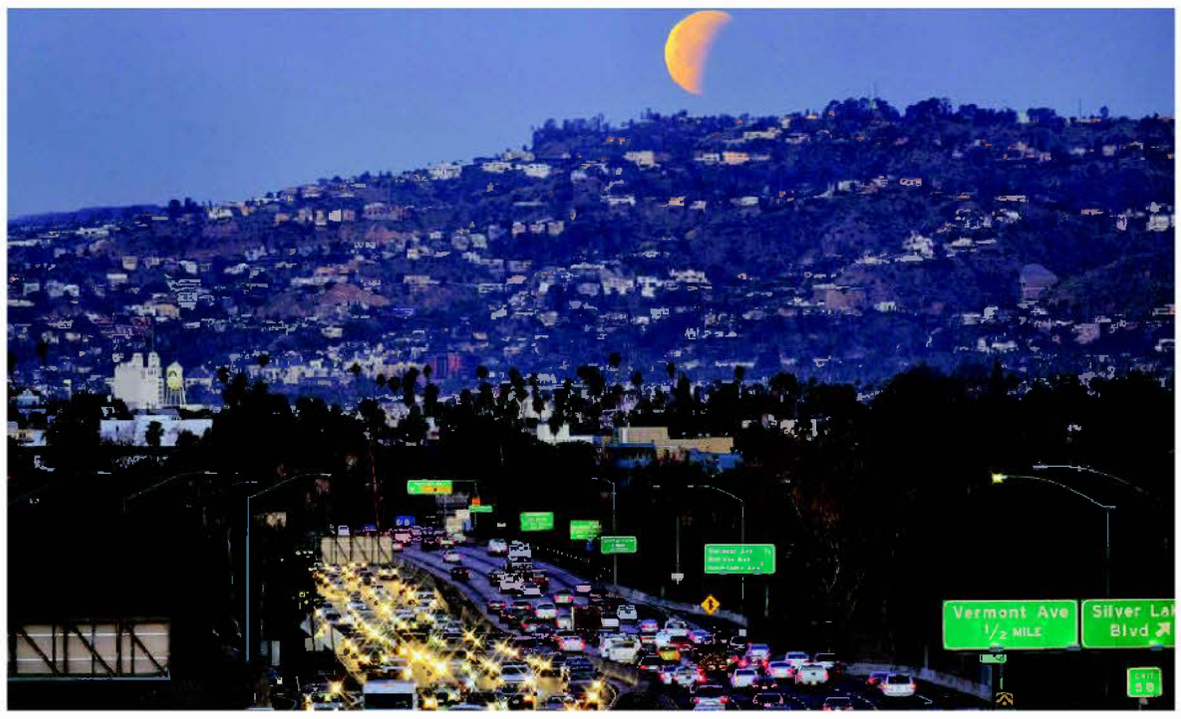

A super blue blood moon is seen setting behind the Hollywood hills in Los Angeles on Wednesday

JUDGE LOYA'S DEATH

Cong threatens nationwide campaign to demand probe

ARCHIS MOHAN
New Delhi, 31 January

The Congress party on Wednesday demanded the Supreme Court (SC) order an "independent" investigation into the "mystery" around the death in 2014 of judge B H Loya, retired district judge Prakash Thombre and Nagpur-based lawyer Shrikant Khandalkar.

The party said it was adding its voice to that of the four SC judges who'd also referred to the case in their conference on January 12, and had said democracy was in peril.

Congress leader Kapil Sibal said the SC or the Bombay High Court should constitute an independent special investigation team (SIT) to probe Loya's death, and those of two others to whom judge Loya had reportedly turned for help.

Sibal said if the Bombay HC failed in its job to take cognisance of these deaths, the Congress would launch an agitation to take the issue to the villages, about how lives of judges and lawyers were at risk. Sibal said the SC-monitored SIT should not have any officers from the Central Bureau of Investigation (CBI) or the National Investigation Agency (NIA).

Loya was hearing the Sohrabuddin Sheikh fake encounter case when he purportedly died of cardiac arrest while in Nagpur to attend the wedding of a colleague's daughter on November 30, 2014.

Sibal said judge Loya's sister had alleged her brother was under pressure to pass an order favourable to the accused and to discharge them, and that he was offered ₹1 billion and a residential flat in Mumbai.

Sibal, party leaders and Satish Uke, a Nagpur-based lawyer and whistle-blower in the case, said Loya's wasn't the only mysterious death in the case. Sibal said Loya had sought help from his friends in Mumbai but couldn't get support. In October 2014, Loya approached Uke through Nagpur lawyer Shrikant Khandalkar and retired district judge Prakash Thombre.

Sibal said Thombre and Khandalkar, and a fourth unknown person, facilitated a video call between Loya and Uke. According to Sibal and Uke, in the video call, Loya named people were pressurising him, including senior judges and leading politicians, to pass a discharge order in the case. In November, 2014, Uke, Thombre and one of their friends travelled to Delhi to take the opinion of a senior lawyer but returned disappointed when the lawyer said the evidence was not sufficient.

On November 30, 2014, Loya died in Nagpur. Sibal said there was evidence available that the judge's security cover, which he was entitled to as a special CBI judge, was withdrawn on November 24. He said there was no record of Loya travelling to Nagpur and there are several other contradictions and infirmities, including in the autopsy report, that arouse suspicion.

Sibal said Khandalkar also told Uke he was receiving threats. A year after judge Loya's death, Khandalkar also died. Sibal said his body was found in the district court premises of Nagpur. He said Khandalkar allegedly fell from the eighth floor of the building on November 29, 2015. He had been missing for two days.

According to Uke, retired judge Thombre had also received threats. Sibal said Thombre died suspiciously while travelling in a train from Nagpur to Bengaluru on May 16, 2016. "There is no FIR (First Information Report) till date in this incident," Sibal said. Sibal said

PAISALO DIGITAL LIMITED

FORMERLY KNOWN AS S. E. INVESTMENTS LIMITED

REGD. OFF: 101, CSC, POCKET 52, NEAR POLICE STATION, CR PARK, NEW DELHI-110019
TEL: +91 11 43518888 FAX: + 91 11 43518816 WEB: www.paisalo.in
CIN: L65921DL1992PLC120483 अर्थः समाजस्य न्यासः

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE) FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2017

(₹in Lacs)

Particulars	Quarter Ended 31.12.2017 (Unaudited)	Nine Months Ended 31.12.2017 (Unaudited)	Quarter Ended 31.12.2016 (Unaudited)
Total income from operation (net)	7690.48	21620.20	6304.17
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2115.20	6577.91	2024.36
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2115.20	6577.91	2024.36
Net Profit/(Loss) for the period after tax	1749.32	5648.12	1606.13
Equity Share Capital	4056.00	4056.00	4056.00
Reserves* (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of Previous Year)	—	—	—
Basic and diluted earning per share (in Rs.) (before and after extraordinary items (not annualised) (Face value of Rs. 10/- each)	4.31	13.93	3.96

* Reserves (excluding Revaluation Reserve) as on 31.03.2017 was Rs. 51356.30 lacs.

Note:
The above is an extract of the detailed Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Company's website i.e. www.paisalo.in and on the Stock Exchanges' websites i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com

Place: New Delhi
Date : 30.01.2018

For and on behalf of Board of Directors
Sd/-
(SUNIL AGARWAL)
Managing Director

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
India's International Bank
www.bankofbaroda.co.in

TENDER NOTICE

Bank of Baroda, Head Office Baroda invites tenders from IBA approved **Paper Manufacturers/Mills/Distributors nominated by Paper Mills** for quoting price bid to supply MICR Security Papers to our empanelled printers for -1-year.

Any Amendments/Modification/Changes including any Addendum in the Tender shall be notified in the Bank's website only. Interested bidder should refer the same before final submission of the proposal.

Last date for submission of Tender is 22-02-2018 before 5.00 P.M. For details log on to **www.bankofbaroda.co.in** and visit the link "Tenders".

Place: Baroda
Date: 01-02-2018

Asstt. General Manager
(Operation & Services),
Head Office, Baroda

Kajaria
TRANSFORMING YOUR WORLD

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2017

(₹ in crores, except per share data)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended 31 December 2017 (Unaudited)	Nine Months Ended 31 December 2017 (Unaudited)	Quarter Ended 31 December 2016 (Unaudited)
1	Income			
	a) Revenue from Operations	661.16	2003.51	677.08
	b) Other income	1.77	5.70	2.10
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	84.25	256.91	85.85
3	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	84.25	257.66	85.85
4	Net Profit for the period after Tax, (after Exceptional and/or Extraordinary items and after minority interest)	54.31	168.99	55.11
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	53.93	167.39	55.11
6	Equity Share Capital (Face value of ₹1/- per share)	15.89	15.89	15.89
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	1159.23 (as on 31 Mar 17)	1159.23 (as on 31 Mar 17)	956.01 (as on 31 Mar 16)
8	Earnings per share (of ₹1/- each) (for continuing and discountinued operations)			
	a) Basic:	3.42	10.63	3.47
	b) Diluted:	3.41	10.60	3.46

Notes:

1 The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 31 January 2018 and have undergone 'Limited Review' by the statutory auditors of the Company.

2 The above results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ('Ind AS') as notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, amended by the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2016, specified under section 133 of the Companies Act, 2013.

3 Additional information on standalone financial results is as follows: ₹ in crores

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended 31 December 2017 (Unaudited)	Nine Months Ended 31 December 2017 (Unaudited)	Quarter Ended 31 December 2016 (Unaudited)
1	Income			
	a) Revenue from Operations	624.05	1926.89	645.40
	b) Other income	5.16	14.80	5.66
2	Net Profit before Tax	90.45	283.26	89.64
3	Net Profit After Tax	59.56	186.64	60.51
4	Total comprehensive income for the period	59.20	185.04	60.51

4 Post the applicability of Goods and Services tax (GST) with effect from 1 July 2017, Revenue from operations are required to be disclosed net of GST in accordance with the requirements of Ind AS. Accordingly the Revenue from operations for the quarter ended and nine months ended 31 December 2017 are not comparable with the corresponding previous quarter/nine months presented in the financial results which are reported inclusive of Excise Duty.

5 The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter and nine months ended 31 December 2017 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results are available on the website of BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the Company's website at www.kajariaceramics.com

Place: New Delhi
Date: 31 January 2018

For and on behalf of the Board
Ashok Kajaria
Chairman & Managing Director

KAJARIA CERAMICS LIMITED
Regd. Office: SF-11, Second floor, JMD Regent Plaza, Mehrauli-Gurgaon Road, Village Sikanderpur Ghosi, Gurgaon -122001 (Haryana)
Corporate Office: J-1/B-1 (Extn), Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044
Ph.: 91-11-26946409 | Fax: 91-11-26946544, 91-11-26946407
CIN: L26924HR1985PLC056150, E-mail: investors@kajariaceramics.com, Website: www.kajariaceramics.com